मोदी की स्मार्ट सिटी में बर्बाद हो गए करोड़ों रुपये

सेक्टर-19 में आधी अधूरी बना कर छोड़ दी स्टार्म वाटर ड्रेनेज पाइप लाइन

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) फरीदाबाद स्मार्ट सिटी भी मोदी के जुमलों की तरह बेकार और आम जनता के लिए परेशानी का सबब साबित हुई है। सेक्टर 19 में बारिश के पानी की निकासी और संरक्षण के लिए ड्रेनेज सिस्टम पर करोड़ों रुपये बर्बाद कर डाले गए। एक साल पहले आधे अधूरे बना कर छोड़े गए नाले आज तक पूरे ही नहीं किए गए।

सेक्टर 19 को फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है। इसके तहत सेक्टर को बारिश में जलभराव से बचाने और रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़ने की योजना तैयार की गई थी। लूट कमाई करने वाले अधिकारियों ने इलाके का अध्ययन किए बिना नाले खुदवाने का काम भी शुरू करवा दिया। बहुत सी जगहों पर नाले के रास्ते में अड़चनें आ रही थीं, कहीं पाइपलाइन बिछी थी तो कहीं अंडरग्राउंड तार डाले हुए थे, कहीं सड़क का जोड़ आ रहा था।

तुरंत ही अड़चन दूर करने के बजाय उस जगह खुदाई छोड़ दी गई और आगे फिर से नाला बना डाला गया। नतीजा यह रहा कि पूरे सेक्टर में नाला टुकड़ों में बना। छूटे हुए हिस्सों को नाले से जोड़ा ही नहीं गया। इस नाले के पानी से ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट (कुआं) भी नहीं बनाया गया। नाला बने हुए एक साल से अधिक का समय बीत चुका है लेकिन यह आज तक चालू नहीं हो सका है।

अधूरे नालों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछा कर फुटपाथ बना दिया गया। स्थानीय निवासी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि फुटपाथ पर घटिया इंटरलाकिंग टाइलें लगाई गईं उनकी टॉप लेयर भी खत्म हो गई है। ऐसे ही एक और निवासी सौरभ सिंह कहते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाकारा अधिकारियों ने नाले की ढाल ही सही नहीं बनाई है, पानी जहां गिरता है वहीं ठहर जाता है। बहाव नहीं होने के कारण एक बरसात में ही यह अधूरा बना नाला गाद और कीचड़ से भर गया है। फुटपाथ उखाड़े बिना इन नालों की सफाई नहीं हो सकती। यानी नाला सफाई के नाम पर फिर करोड़ों रुपयों का बजट बनाया जाएगा।

तकनीकी जानकारों के अनुसार नाला निर्माण में भी खेल किया गया। उनके अनुसार सीमेंट, ईंट और कंक्रीट से बनाए गए इस नाले में जितना खर्च किया गया है उससे कम लागत और मेहनत में यहां सीमेंट पाइप डाले जा सकते थे। वर्षा जल संरक्षण के लिए मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी सीमेंट पाइप से ही नाले बनाए गए हैं जो ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इसमें भी कमीशन वाली सीमेंट, ईंट आदि निर्माण सामग्री खपाई गई है। यही कारण है कि कुछ ही समय बाद इंटरलॉकिंग टाइल्स की टॉप लेयर खत्म हो गई। नेत्रहीन पैदल यात्रियों की मदद के लिए लगाई गई पीले रंग की तेन्जी ब्लॉक पट्टी भी गायब हो चुकी है।

हाल ही में डीसी ने स्मार्ट सिटी के सभी प्रोजेक्ट जून में समाप्त करने का आदेश जारी किया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनना और उससे जुड़ना तो दूर जून के अंत तक तो यह नाला बनकर तैयार हो जाए यही बड़ी बात होगी।

संदर्भवश बता दें कि जब फरीदाबाद बसाया गया तब से यहां स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, हूडा के सेक्टर हों या नगर निगम का इलाका स्टार्म वाटर लाइनें आज तक कहीं चलीं नहीं। बारिश में चोक और जलभराव की समस्या हर कहीं देखी जा सकती है। पहले से बना जो ड्रेनेज सिस्टम नाकारा अधिकारियों के कारण नहीं चल सका उसी तरह सेक्टर १९ का यह स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम भी फ्लॉप ही साबित होगा।

लघु सचिवालय में पार्किंग की जगह नहीं, ठेका छोड़ा 26 लाख में

डीसीपी ट्रैफिक ने किया विरोध

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) कितना हास्यास्पद है, लघु सचिवालय के पास वाहन पार्किंग के नाम पर इंच भर भी जगह नहीं है और पार्किंग का ठेका एक वर्ष के लिये 26 लाख में, जिला प्रशासन द्वारा छोड़ दिया गया है। जाहिर है ऐसे में ठेकेदार लघु सचिवालय के चारों ओर की सड़कों पर वाहन खड़े करने वालों से वसूली करेगा।

सेक्टर 12 स्थित इस लघु सचिवालय के साथ न्यायिक परिसर, 'हूडा' ऑफिस तथा खाद्य एवं आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण कार्यालय है। इनमें हजारों लोग प्रति दिन आते हैं। इसके परिणाम स्वरूप चारों ओर की सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। एक ओर तो पुलिस का कर्त्तव्य है कि सड़क पर खड़े वाहनों का चालान करे और दूसरी ओर ज़िला प्रशासन उन्हीं सड़कों पर वाहन खड़े करने का भारी-भरकम ठेका छोड़ रहा है। जाहिर है कि इससे इन सड़कों पर आवागमन दूभर हो जाता है। संकटकालीन स्थिति में एम्बुलेंस आदि का भी निकलना कठिन हो जाता है।

यूं तो यह स्थिति बीते दसियों बरस से चली आ रही है जिसकी मौन स्वीकृति पुलिस ने भी दे रखी थी। परन्तु अब पहली बार किसी पुलिस अधिकारी ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए विरोध किया है। नव नियुक्त डीसीपी ट्रैफिक अमित यशवर्धन ने पार्किंग ठेकेदार को इस बाबत कड़ी हिदायत जारी करने की बात कही है। लगता है पहली बार कोई रीढ़ की हड्डी वाला पुलिस अधिकारी यहां प्रकट हुआ है। अब देखना यह है कि ज़िला प्रशासन के सामने यह रीढ़ कब तक सीधी खड़ी रह पायेगी?

समस्या की जड़ में दूरदृष्टि का अभाव

डीसीपी ट्रैफिक अमित

वर्ष 1985-86 में यहां लघु सचिवालय के नाम से पहली पांच मंजिला बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। कुछ समय बाद इसमें ज़िला अदालतों को भी घुसेड़ दिया गया।

उस समय शासन-प्रशासन चलाने वालों को इस बात की समझ नहीं थी कि आने वाले समय में वाहन पार्किंग की समस्या भी होगी। यदि उसी समय उस बिल्डिंग के नीचे 400-500 वाहन पार्किंग के लिये बेसमेंट बनाई होती तो यह समस्या इतनी विकराल न होती।

सन् 2004-5 में मौजूदा लघु सचिवालय का निर्माण किया गया। इसमें तहसील, एसडीएम आदि के कार्यालय सहित तमाम दफ्तरों को लाया गया। यहां फिर दूरदृष्टि का अभाव नज़र आया। इस बिल्डिंग के नीचे पार्किंग के लिये जो बेसमेंट बनाई गई थी उसमें भी तमाम कार्यालयों का सामान एवं रिकार्ड इत्यादि भर दिया गया और तो और ये नई बिल्डिंग भी इतनी अपर्याप्त बनाई गई कि इसमें न तो शिक्षा विभाग के दफ्तर समा सके न ही ज़िला कोषागार, समाज कल्याण के दफ्तर को भी यहां से निकालना पड़ा, पुलिस विभाग के लिये सेक्टर 21 में नई बिल्डिंग तलाशी गई। कुल मिलाकर शासन-प्रशासन केवल आज भर की सोचता है कल को क्या स्थिति होगी इसकी कोई समझ इन्हें कभी नहीं रही।

करीब 12 वर्ष पूर्व वकीलों के चेम्बर बनाते वक्त भी किसी की बुद्धि ने काम नहीं किया कि पार्किंग के लिये बेसमेंट भी बना दिया जाए। यही स्थिति नवनिर्मित ज़िला न्यायिक भवन की भी है।

बीते 12 साल में एमसीएफ़ ने तो 'लगा दिये रेन-हार्वेस्टर'

अब बारी है एफएमडीए की

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) बीते लगभग 12 साल में नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपये खर्च कर अनेकों रेन हार्वेस्टर लगा दिये, बताये जाते हैं। मजे की बात तो यह है कि इनके द्वारा एक बूंद भी बरसाती पानी ज़मीन में नहीं उतर पाया है। जाहिर है हरामखोर एवं रिश्वतखोर अधिकारियों ने केवल टेंडर पास करके बिलों का भुगतान करके अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली।

उनकी इस लूट एवं सार्वजनिक डकैती की जांच करके लुटेरों को पकड़ने की बजाय अब यही काम एफएमडीए (फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण) के द्वारा कराये जाने की बात कही जा रही है। किसी से छिपा नहीं है कि एफएमडीए में भी कोई दूध के धुले इंजीनियर नहीं लगाये गये हैं। यहां भी वही सब हैं जो नगर निगम व 'हूडा' में डकैतियां मार कर रिटायर होने के बाद, नई पारी खेलने के लिये एफएमडीए में आ जुटे हैं। कुछ समय बाद जब ये भी लूट-मार करके निकल लेंगे तब सरकार कोई नया प्राधिकरण खड़ा करके उसे भी डकैती मारने का पूरा अवसर प्रदान करेगी।

संदर्भवश सुधी पाठक जान लें कि करीब छः वर्ष पूर्व सीएम खट्टर ने फरीदाबाद में एक हजार रेन-हार्वेस्टर लगाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक बात जबानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ पाई है।

सीएम खट्टर की घोषणा से प्रेरित होकर एक समाजसेवी एवं पूर्व पार्षद योगेश ढींगड़ा ने एमसीएफ़ से बाकायदा परमीशन लेकर मैट्रो रोड स्थित रोज़ गार्डन में लाखों रुपया खर्च करके एक रेन हार्वेस्टर लगाने का काम शुरू किया था।

ज्यों ही इसकी भनक स्थानीय विधायक सीमा त्रिखा को लगी, उन्होंने काम को बीच में ही रुकवा दिया। इससे स्वतः सिद्ध है कि भाजपाई न खुद कुछ करते हैं और न ही दूसरों को कुछ करने देते हैं।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।